सुविचार

जीवन का दर्शन समझना इतना आसान नहीं। कुछ नोबेल पुरस्कार और इसके समकक्ष कोई दूसरा सम्मान पाने वालों से ऐसे लोग अपनी जिन्दगी अधिक आनंद से बिताते हैं जिन्हें नोबेल या इसके समकक्ष पुरस्कारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता।

सुभाष चंद्र लखेड़ा, सान होजे, कैलिफोर्निया

संपादकीय

भूख और बर्बादी के बीच का भारत : थाली में सिमटा हमारा नैतिक पतन

(प्रथम पृष्ठ से जारी)

भोजन की बर्बादी केवल थाली तक सीमित नहीं, इसका सबसे गहरा प्रहार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर होता है। अनुपयोगी भोजन कचरा भराव स्थलों में सड़कर मीथेन गैस छोड़ता है, जो भूमंडलीय तापवृद्धि की प्रमुख वजह है। वैश्विक स्तर पर खाद्य अपव्यय कुल हरितगृह गैस उत्सर्जन का 8 से 10 प्रतिशत हिस्सा है, जो विमानन उद्योग से भी अधिक है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह केवल अन्न नहीं, बल्कि पानी, बिजली, डीजल, उर्वरक, परिवहन, भंडारण और किसानों के श्रम का भी अपव्यय है। अनुमान है कि इससे भारत को हर वर्ष डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होता है। इतनी राशि से हजारों विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई और पोषण योजनाएं साकार हो सकती हैं। सच यह है कि हम भोजन नहीं, अपने भविष्य की संभावनाएं कूड़ेदान में फेंक रहे हैं।

विडंबना यह है कि यह संकट तकनीक का नहीं, मूल्यों के क्षरण का परिणाम है। जिस समाज ने अन्नपूर्णा को देवी माना, वहीं अन्न का अपमान सामान्य होता जा रहा है। एक ओर करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी ओर दावतों का भोजन कूड़ेदान में पहुंच रहा है। यह केवल आर्थिक असमानता नहीं, सामाजिक संवेदनहीनता का भी प्रमाण है। विकसित देशों में 'डॉगी बैग' जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है, जबकि भारत में इसे आज भी संकोच से देखा जाता है। अनेक होटलों का बचा भोजन सुरक्षित व्यवस्था से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। घरों में सही मात्रा में भोजन पकाना, बचे भोजन का पुनः उपयोग, बेहतर शीतक प्रबंधन और पहले से उपलब्ध सामग्री का उपयोग अपव्यय को काफी घटा सकता है। आखिर, संस्कारों की पहचान पूजा से नहीं, अन्न के सम्मान से होती है।

समस्या जितनी व्यापक है, समाधान भी उतने ही व्यावहारिक हैं। कई होटल और भोजन-व्यवस्थापक अब 'शून्य अपव्यय विवाह पैकेज' अपना रहे हैं, जिनमें अतिथियों की संख्या के अनुसार भोजन का वैज्ञानिक आकलन होता है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं विवाह और होटलों का बचा सुरक्षित भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। यह केवल सेवा नहीं, संसाधनों के सम्मान की संस्कृति है। सरकार को बड़े आयोजनों में खाद्य अपव्यय रोकने के लिए जनजागरूकता, प्रभावी नियम और कर प्रोत्साहन जैसे कदम उठाने होंगे। विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में खाद्य अपव्यय, पोषण और संसाधन संरक्षण को शामिल करना समय की मांग है, ताकि नई पीढ़ी इसे व्यवहार में उतारे। जब समाज इसे आदत नहीं, राष्ट्रीय दायित्व मानेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।

आज प्रौद्योगिकी भी इस चुनौती का प्रभावी समाधान बन सकती है। स्मार्ट फ्रिज भोजन की उपयोग अवधि बताकर बर्बादी रोक सकते हैं, जबकि मोबाइल ऐप्स से बचा भोजन तुरंत डोनेशन नेटवर्क तक पहुंचाया जा सकता है। बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विवाह, होटल और बड़े आयोजनों के लिए आवश्यकता के अनुरूप भोजन का सटीक आकलन संभव बना रहे हैं। नगर निकाय, होटल उद्योग, खाद्य कंपनियां और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर खाद्य अपव्यय को काफी घटा सकती हैं। कई देशों ने ऐसे उपायों से सफलता पाई है। भारत के पास तकनीक के साथ संस्कारों की पूंजी भी है; आवश्यकता केवल दोनों के समन्वय की है। अन्न को संसाधन नहीं, संस्कार मानते ही समाधान व्यवहार बन जाएगा। समाधान की शुरुआत किसी कानून से नहीं, हमारी थाली से होगी। हर परिवार, हर मेहमान और हर होटल मालिक को समझना होगा कि एक दाना भी बर्बाद करना राष्ट्र की संपत्ति को लुटाना है। जब तक 'ज्यादा परोसो' की संस्कृति 'जितना जरूरी, उतना ही' में नहीं बदलेगी, विकास के दावे अधूरे रहेंगे। खाद्य अपव्यय रोकना केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि आर्थिक विवेक, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारतीय सभ्यता की पुनर्परिभाषा का संकल्प है। अन्न का सम्मान होगा, तो भूख घटेगी, प्रदूषण कम होगा, संसाधन बचेंगे और विकास अधिक मानवीय बनेगा। किसी राष्ट्र की समृद्धि थालियों की भव्यता से नहीं, उनमें परोसे हर दाने के सम्मान से मापी जाती है; भारत को अब यही कसौटी अपनानी होगी।

शिक्षाविद् बड़वानी (मप्र)

विभागीय कार्ययोजना बनाकर जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ जिले के विकास को दें गति-सांसद श्रीमती चौहान

सांसद श्रीमती अनीता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का किया गया आयोजन

आलीराजपुर। झाबुआ-रतलाम लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती अनीता चौहान की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजरी बाई खरत, जिला अध्यक्ष श्री मकू परवाल सहित समस्त जनपद पंचायत सदस्य,जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सांसद श्रीमती चौहान ने पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), कृषि विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं भावांतर योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जिले में हैंडपंपों की स्थिति, खराब एवं सुधारे गए हैंडपंपों तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं और प्रगतिरत कार्यों सहित विभिन्न विभागों में कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। सांसद श्रीमती चौहान ने सभी अधिकारियों को अपनी विभागीय कार्ययोजना बनाकर कार्य करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिले के विकास को गति देने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने उप संचालक कृषि को खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था के संबंध में गांव-गांव में किसानों को जागरूक करने और उनसे निरंतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को नियमानुसार एवं समय पर खाद उपलब्ध हो और वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने खाद वितरण केंद्रों के समीप कियोस्क सेंटर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए, जिससे किसानों को ई-टोकन जनरेट करने में सुविधा हो। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद श्रीमती चौहान ने नवीन ग्रिड निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी कर उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता से विद्युतीकरण कार्य करने को कहा, जहां अभी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक को निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद श्रीमती चौहान ने जिले के जीर्ण-शीर्ण आंगनवाड़ी भवनों का चिन्हांकन कर सूची तैयार करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित दावा-आपत्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण एजेंसियों को सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। पीआईयू विभाग के निर्माण कार्यों को भी गति देते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने अधिकारियों को जिले के सभी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों के सूचना पटल पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं बीईओ के मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाएं, ताकि छात्र-छात्राएं किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सीधे अवगत करा सकें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो।

नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिव्यांगता पेंशन एवं गरीबी रेखा के कूपन बंद होने के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन किया

सनावद(विजय गुप्ता) नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिव्यांगता पेंशन एवं गरीबी रेखा के कूपन बंद होने के विरोध में धरना देखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देकर इसे शीघ्र शुरू करने और गरीबों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल बंटी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा अवस्था दिव्यांगता पेंशन नहीं डाली जा रही है। जिससे गरीब एवं मजदूर वर्ग को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ा है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के कूपन को भी बंद कर दिया गया है। इससे गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। नगर के आसपास के वार्डों से आई हुई महिलाओं ने बताया कि गरीबी रेखा के कूपन बंद करने से जहां राशन के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। वही वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगता पेंशन के कार्यों में भी लेटलतीफी होती है।।जिससे नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार की इस नीति से गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। मंडलम अध्यक्ष मुकेश कौशल ने बताया कि भाजपा सरकार गरीबों का दिखाने की बड़ी-बड़ी बातें करती है। लेकिन जमीनी हकीकत में वह गरीबों को होने वाली परेशानियों से अनजान है। और उन्हें परेशान कर आम नागरिक मजदूर महिला एवं गरीबों का ठग रही है। पूर्व पार्षद शेख साकेरिन ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबी रेखा के कूपन बंद करने के बाद जहां नगर के माध्यम वार्डों के लोग परेशान है। शासन द्वारा इसको लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे उनकी लड़ाई अब कांग्रेस अपने दम पर लड़कर शहर ओर ग्राम में चल रही लापरवाही को लोगों के सामने लाएगी। आंदोलन के दौरान नकुल पटेल पार्षद पवन इंगला जय शिंदे पूर्व पार्षद गौतम विधार्थी हरमिंदर सिंह कपूर जरारा एहमद महेश पटेल भीमसिंह चौहान सुनील व्यास आफताब हिलाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन नायब तहसीलदार संतोष कुशवाह को देकर सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिव्यांग पेंशन एवं अन्य पेंशन शुरू जल्द शुरू करने की मांग की है।

साइकिल वितरित की गई

बाजना। बाजना एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मलवासी में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शासन की योजना अनुसार साइकिल वितरित की गई जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह जाट ,रावटी सरपंच संजय झोड़ियां, उपाध्यक्ष भेरकी बाई डीडोड़, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अरविंद पोरवाल, आदिवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष सुरेश सिंघाड़, ग्रामीण जन एवं पालक गण और समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा आभार प्रधानाध्यापक व्दारा माना गया।

गलती करना अपराध नहीं है गलती को बार-बार दोहराना अपराध है।...अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी

सोनकच्छजैन ग्रन्थ स्वाध्याय समयसार जिनकी गाथाओं को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन का विषय बनाया जो हमें सिखा रहा है कि यह आत्मा जब अपने से भिन्न पदार्थ को परवस्तु जान लेता है या जब तक हम परवस्तु को अपना मान रहे हैं समझाते मिथ्यात्व अपने अंदर बैठा है। यह ग्रन्थ हमें दिशा बोध देता है कि हरपल अपने आत्मकल्याण को ध्यान में रखना चाहिए यह बात गुरुदेव ने प्रतिदिन होने वाले जिनवाणी शास्त्र ग्रन्थ समयसार के स्वाध्याय के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाते हुए कही उन्होंने कहा कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और कायोत्सर्ग यह तीन बाते आप का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रतिक्रमण अर्थात पूर्व में जो गलती हमसे हुई हो उसे स्वीकार कर लेना। लेकिन उस गलती को इस भाव के साथ स्वीकार करे कि अब कभी हम वह गलती नहीं करेंगे। गलती करना अपराध नहीं है गलती को बार-बार करना अपराध है। इसलिए यहां पूज्यसंत कह रहे है पाप का प्रायश्चित है पर अपराध का नहीं क्योंकि पाप की सजा कर्म देता है अपराध की सजा कानून इसी तरह प्रत्याख्यान का अर्थात जो गलतियां हमने भविष्य में की है अब हम संकल्प पूर्वक अब कभी उस गलती को नहीं दोहरायेंगे। वही कायोत्सर्ग अर्थात सहन करने का मार्ग वह ध्यान मुद्रा जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए उस ध्यान मुद्रा का खंडन न हो। व्यक्ति को आज के समय में ध्यान में ध्यान देना चाहिए लेकिन उसका ध्यान कही ओर लगा हुआ है। इसलिए परवस्तु को अपना मान लेना इससे सूक्ष्म कोई मिथ्यात्व ओर कोई हो नहीं सकता है। हमे हर पल यह सोचना चाहिए कि जो हमें दिख रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है और जिससे संबंध है वो दिख नहीं रहा है।

शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई - विधायक कमलेश्वर डोडियार ने स्वकसे की जांच की मांग.- युवतियों ने औद्योगिक क्षेत्र और सरवन थाने में दी थी शिकायत, मामला ठंडे बस्ते में

नौकरी दिलाने के नाम पर 4 युवतियों से की ठगी

सैलाना। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवतियों से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। सैलाना विधानसभा क्षेत्र की चार युवतियों से ने नौकरी का झांसा देकर लगभग ?23,000 हजार रुपए की प्रत्येक से अलग-अलग राशि ठग की और नही उनको कोई नोकरी दी । पीड़िताओं द्वारा इस संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र और थाना सरवन में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने रतलाम पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला-विधायक को दिए गए आवेदन में रानू मईड़ा, रीना पारगी, संगीता निनामा और पायल मईड़ा ने बताया कि सोना नाम की एक लडकी ने उन्हें नौकरी दिलाने का वादा कर उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद न तो नौकरी दी गई और न ही रकम वापस की गई। जिसकी शिकायत लेकर पीड़िताएं पहले थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पहुंची, फिर थाना सरवन गईं, लेकिन दोनों जगह उनकी शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पीड़िताओं में पुलिस-प्रशासन के प्रति निराशा बढ़ गई है। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने एसपी को लिखे पत्र में कहा कि यह सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया गंभीर अपराध है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे तत्व अन्य युवाओं को भी अपना शिकार बनाएंगे।उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की वरिष्ठ अधिकारी से समयबद्ध जांच कराई जाए, आरोपियों पर बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई हो।शिकायत के बाद भी लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच हो। पीड़िताओं को न्याय दिलाकर उनकी ठगी गई राशि वापस कराई जाए। विधायक ने भरोसा जताया कि एसपी इस मामले को प्राथमिकता से लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास बना रहे।

बाल यौन शोषण से संरक्षण एवं महिला अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

आलीराजपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से जनपद पंचायत भवन चन्द्रशेखर आजाद नगर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को यौन शोषण, तस्करी एवं अन्य अपराधों से संरक्षण के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने बाल अधिकार, बाल विवाह निषेध, शिक्षा का अधिकार, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, महिलाओं के संपत्ति अधिकार एवं साइबर सुरक्षा पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, पैरालीगल वॉलेंटियर्स तथा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही

चार राज्यों के भील बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास की उठाई मांग

विधायक डोडियार ने पृथक भीलप्रदेश राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

सैलाना । क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विस्तृत ज्ञापन भेजकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के भील बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास तथा पृथक भील प्रदेश के गठन के संबंध में आवश्यक पहल करने की मांग की है। विधायक डोडियार ने कहा कि भील समाज लंबे समय से अपने अधिकारों, सम्मान और संतुलित विकास की मांग करता आ रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी अंचल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं के मामले में पिछड़े हुए हैं। अपने ज्ञापन में विधायक डोडियार ने उल्लेख किया कि भील बहुल क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों का अभाव आदिवासी समाज की प्रगति में बड़ी बाधा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि भील अंचलों में एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की जाए, ताकि

स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज एवं दीर्घकालीन विकास योजना तैयार की जाए। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मध्यप्रदेश सहित संबंधित राज्यों के भील बहुल क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कराने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए। समिति की अनुशंसाओं एवं संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श के बाद यदि उपयुक्त हो तो संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत पृथक भील प्रदेश के गठन की प्रक्रिया पर विचार किया जाए। डोडियार ने कहा कि उनका उद्देश्य आदिवासी समाज को न्याय दिलाना, क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना और भील बहुल क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने केंद्र सरकार से जनहित और आदिवासी समाज के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सकारात्मक एवं न्यायोचित निर्णय लेने का आग्रह किया।